भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 253
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन

253. श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्री संजय दिना पाटीलः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन लागू कर रही है और यदि हां, तो इस मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र में किए गए प्रमुख अनुसंधान और विकास पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मिशन के अंतर्गत दलहन अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रसार में शामिल महाराष्ट्र के कृषि अनुसंधान संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और विश्वविद्यालयों के नामों और स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में दलहन की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल, प्राप्त उत्पादन तथा अनुमानित कमी, यदि कोई हो, कितनी है तथा इस अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) महाराष्ट्र में दलहन की खेती को बढ़ावा देने और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए किसानों और अनुसंधान संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के प्रभाव का उपज में सुधार, आत्मनिर्भरता के स्तर और आयात पर निर्भरता में कमी के संदर्भ में कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में दलहन अनुसंधान को मजबूत करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ कोई सहयोगात्मक प्रयास किए हैं; और

(छ) महाराष्ट्र में किसानों के बीच बेहतर दालों की किस्मों और दक्ष सिंचाई प्रणालियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर, 2025 को 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025-26 से वर्ष 2030-31 तक छह वर्ष की अवधि में दलहन में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, जिसका वित्तीय परिव्यय 11,440 करोड़ रुपए है। इस मिशन का कार्यान्वयन महाराष्ट्र सहित 28 राज्यों और 2 संघ राज्य-क्षेत्रों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में किया जा रहा है।

इस मिशन का उद्देश्य तुअर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों के लिए जलवायु अनुकूल बीजों के उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ावा देना, दलहन खेती के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना, फसलोपरांत भंडारण एवं प्रबंधन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के मानदंडों के अनुसार आगामी चार वर्षों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) द्वारा तुअर, उड़द, मसूर की खरीद सुनिश्चित करना है।

देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), आईसीएआर-भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर और इसके चार क्षेत्रीय केंद्रों भोपाल, धारवाड़, बीकानेर और खोरधा में दलहन फसलों पर कार्यनीतिक अनुसंधान कर रही है और इसके साथ ही राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से खरीफ और रबी दलहन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के माध्यम से अनुप्रयुक्त अनुसंधान भी कर रही है, ताकि दलहन की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए स्थान-विशिष्ट उच्च उपज वाली किस्मों और मैचिंग उत्पादन प्रौद्योगिकी पैकेजों को विकसित किया जा सके।

महाराष्ट्र राज्य की एग्रो-इकोलॉजी के अनुसार दलहन पर अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने के लिए, आईसीएआर खरीफ और रबी दलहन पर आईसीएआर के एआईसीआरपी के तहत राज्य के चार कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों नामतः वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभणी; डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला; महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी; और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रॉम्बे, मुंबई के साथ सहयोग कर रहा है।

विगत तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण भारत और महाराष्ट्र राज्य के लिए कुल दलहन का क्षेत्र, उत्पादन और उपज निम्नानुसार है:

राज्य	**क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)**			**उत्पादन (लाख टन में)**			**उपज (किग्रा/हेक्टेयर)**		
	2022-23	**2023-24**	**2024-25**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
अखिल भारतीय	289.01	275.05	277.20	260.58	242.46	256.83	902	881	926
महाराष्ट्र	49.94	44.32	49.87	46.35	40.08	50.35	928	904	1010

स्रोत: यूपीएजी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

(घ) से (छ): आईसीएआर ने राज्य में दलहन उत्पादन में सुधार हेतु खरीफ और रबी दलहन पर दो अखिल भारतीय समन्वित फसल अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) के अंतर्गत महाराष्ट्र में सहयोगी भागीदारों को वर्ष 2023-24 में 457.5 लाख रुपये, वर्ष 2024-25 में 493.2 लाख रुपये और वर्ष 2025-26 में नवंबर 2025 तक 391.8 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में दलहन पर 11 बीज केंद्र संचालित हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' के तहत ब्रीडर सीड और अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज के संवर्धन और वितरण, बीज केंद्रों को सुदृढ़ करने, नवीनतम फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, सीड किट, क्षमता निर्माण, फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। नवीनतम किस्मों और उत्पादन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए, विश्वविद्यालयों के संबद्ध वैज्ञानिक किसानों के खेतों में दलहन पर फ्रंटलाइन प्रदर्शन का आयोजन करते हैं। विगत तीन वर्षों (वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक) के दौरान खरीफ और रबी दलहन पर एआईसीआरपी के तहत उपज अंतर का आकलन करने के लिए किसानों के खेतों में लगभग 834 फ्रंटलाइन प्रदर्शन आयोजित किए गए। इसके अलावा, राज्य में दलहन को बढ़ावा देने के लिए किसान मेले, किसान-वैज्ञानिक पारस्परिक-चर्चा, किसानों के लिए एक्सपोजर दौरे का आयोजन किया जाता है, परामर्शिका जारी की जाती है तथा किसान हितैषी साहित्य का वितरण भी किया जाता है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2015-16 से महाराष्ट्र सहित देशभर में केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस), प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) का कार्यान्वयन कर रहा है। विगत 10 वर्षों (वर्ष 2015-16 से वर्ष 2024-25 तक) के दौरान महाराष्ट्र में 11.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया है।

*****